भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *196

13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन में कम/शून्य कार्बन उत्सर्जन हेतु नीति

***196. श्री रविचंद्र वद्दीराजू:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग को कम कार्बन उत्सर्जन या लगभग शून्य उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन वाले उद्योग में परिवर्तित होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई नीति अपनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे इस्पात विनिर्माताओं के लिए, उनकी विनिर्माण प्रक्रियाओं में बायोचार और अन्य वहनीय सामग्रियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए, कोई प्रोत्साहन या समर्थन तंत्र विद्यमान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने हरित सार्वजनिक खरीद (जीपीपी) जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है

*****

"इस्पात उत्पादन के दौरान कम/शून्य-कार्बन उत्सर्जन की नीति" के संबंध में श्री रविचंद्र वद्दीराजू, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 13/12/2024 को उत्तर के लिए प्रस्तुत किए गए राज्य सभा तारांकित (*) प्रश्न संख्या *196 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में सदर्भित विवरण

(क) और (ख): कम कार्बन या लगभग शून्य उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन के संक्रमण के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण प्रक्रिया में स्थायी सामग्री के उपयोग में सहायता के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई पहलें और नीतियां निम्नानुसार हैं:-

(1) इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान'' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है और इस्पात क्षेत्र के अकार्बनीकरण के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है तथा इसके लिए रणनीति, कार्य योजना और रोडमैप तैयार करती है।

(2) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इसके उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है। इस्पात मंत्रालय इस मिशन में एक हितधारक है और इस मिशन के तहत कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए वर्टिकल शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डारेक्ट रिड्यूस आयरन (डीआरआई) के उत्पादन के लिए दो पायलट परियोजनाएं और मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए एक पॉयलट परियोजना प्रदान की है।

(3) कच्चे माल के रूप में इस्पात स्क्रैप का उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस्पात मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 में घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मोटरयान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम सितंबर, 2021 इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना करती है।

(4) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

(5) राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना इस्पात उद्योग को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित रिपोर्ट में लौह एवं इस्पात उद्योग के अकार्बनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **बायोचार** को पद्धितियों (लीवरों) में से एक के रूप में चिन्हित किया है।

(ग) माननीय प्रधानमंत्री ने ग्लासको में आयोजित कोप 26 बैठक में घोषणा की है कि भारत वर्ष 2070 तक निवल शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस्पात मंत्रालय इस वक्तव्य के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी सभी कदम उठा रहा है।

*****